

आय कर संदर्भ
समक्ष न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित और न्यायमूर्ति भूपिंदर सिंह दिल्ली,

द कमिश्नर ऑफ इनकम-टैक्स, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली-III नई दिल्ली,-आवेदक
बनाम

सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड-प्रतिवादी आयकर संदर्भ सं. 1971 का 24.

2 अगस्त, 1972।

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (XLVI of 1948)- धारा 2,4 और 5-आय-कर अधिनियम (1961 का 13)-धारा 28-बेची गई वस्तु पर विक्रय-कर-चाहे वह वस्तु की कीमत का घटक हिस्सा हो-किसी विक्रेता द्वारा विक्रय-कर की प्राप्ति जो सरकार को ऐसे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है-चाहे आयकर अधिनियम की धारा 28 के प्रयोजन के लिए व्यापार रसीद-वस्तु के क्रेता का विक्रेता से कर का दावा करने का अधिकार-क्या यह रसीद के स्वरूप को प्रभावित करता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि कराधान की घटना का उपबंध पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन किया गया है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक विक्रेता, जिसका सकल कारोबार कर योग्य मात्रा से अधिक है, अधिनियम के अधीन बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए दायी है। यह माल बेचने वाला विक्रेता है जो अधिनियम के तहत निर्धारित कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए मूल्यवान विचार विक्रेता द्वारा खरीदार से प्राप्त कुल राशि है। विक्रेता इस तथ्य की परवाह किए बिना बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या वह माल को खरीदार को देने के लिए माल की कीमत के साथ बिक्री-कर वसूलने का विकल्प चुनता है या नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि बिक्री कर बिक्री मूल्य का एक अभिन्न अंग है। चूंकि कर की घटना निर्धारिती पर है और खरीदार अधिकारियों को बिक्री कर के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए, बिक्री मूल्य की सही सामग्री कुल है निर्धारिती द्वारा क्रेता से प्राप्त प्रतिफल। केवल यह तथ्य कि बिक्री-कर को बिक्री कर के रूप में दिखाया गया है, उसके व्यापार अनुबंध के चरित्र के अनुबंध को नकारता नहीं है जिसमें एक पक्ष बेचता है और दूसरा पक्ष उस माल को खरीदता है जिसमें व्यवसाय या व्यापार किया जाता है। यदि विक्रेता सरकार को बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है तो यह पूरी तरह से महत्वहीन है। यह तथ्य कि खरीदार बाद में किसी समय विक्रेता से कर वापस लेने का दावा करने का हकदार है, रसीद के कानूनी चरित्र को नहीं बदलेगा। अतः किसी निर्धारिती द्वारा सुसंगत निर्धारण वर्ष के दौरान प्राप्त आय-कर की कुल राशि, जिसमें सरकार को अदा नहीं किया गया विक्रय कर भी शामिल है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 (i) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए एक व्यापारिक रसीद है। तथापि, यदि और जब निर्धारिती क्रेताओं को उनकी मांग पर प्रश्नगत राशि का भुगतान करता है, तो निर्धारिती निर्धारण वर्ष में राहत मांगने का हकदार हो सकता है जिसमें प्रश्नगत राशि का भुगतान किया जाता है, लेकिन जहां तक निर्धारण वर्ष का संबंध है जिसमें राशि प्राप्त की गई थी, बिक्री कर सहित निर्धारिती द्वारा प्राप्त कुल राशि एक व्यापारिक रसीद है और आयकर के लिए उत्तरदायी है।

I.T.A से उत्पन्न होने वाले कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर उच्च न्यायालय की राय के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच द्वारा दिया गया संदर्भ। नं. निर्धारण वर्ष के लिए 1968-69 का 8276:-"चाहे तथ्यों पर

और मामले की परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण को निर्धारण से रुपये की राशि को बाहर करने में कानून में उचित ठहराया गया था। 4, 155 बिक्री कर जमा का प्रतिनिधित्व करते हैं?

याचिकाकर्ता की ओर से डी. एन. अवस्थी और बी. एस. गुप्ता, अधिवक्ता।

एच. एल. सिब्बल, अधिवक्ता, एस. सी. सिब्बल, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता।

फैसला

दिल्लन, जे. -राजस्व के संदर्भ में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ द्वारा निर्दिष्ट विधि का प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में है:- "क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर, न्यायाधिकरण को आकलन से 500 करोड़ रुपये की राशि को बाहर करने में विधि में न्यायसंगत ठहराया गया था। 4, 155 बिक्री कर जमा का प्रतिनिधित्व करते हैं?"

(2) संक्षेप में कहा गया है कि इस संदर्भ को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि एम/एस। सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड, यमुनानगर, निर्धारिती फर्म ने वर्ष 1956 से पहले अपने ग्राहकों से रु। 4, 155 बिक्री-कर के रूप में, लेकिन बिक्री-कर के भुगतान के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसे लेन-देन पर कोई बिक्री-कर देय नहीं था। निर्धारिती फर्म ने फिर इस राशि को वर्ष 1963-64 के लिए लाभ और हानि खाते में वापस लिख दिया। आयकर अधिकारी, पटियाला ने वर्ष 1963-64 के लिए फर्म का मूल्यांकन करते समय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह राशि निर्धारिती फर्म द्वारा व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त की गई थी, इसलिए उक्त राशि कर योग्य थी। इस आदेश के विरुद्ध व्यथित निर्धारिती फर्म ने दिनांक 18 फरवरी, 1967 को आयकर, ए रेंज, पटियाला के अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने इस राशि के संबंध में आयकर अधिकारी के आदेशों को बरकरार रखा-उनके दिनांक 4 मई, 1968 के आदेश के अनुसार। निर्धारिती फर्म का यह तर्क कि विचाराधीन राशि निर्धारिती फर्म के पास न्यासी के रूप में जमा की गई थी और खरीदारों द्वारा किसी भी समय इसकी मांग की जा सकती थी, इसलिए उक्त राशि पर कर नहीं लगाया जा सकता था, अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलीय सहायक आयुक्त ने निर्धारिती द्वारा भरोसा किए गए अधिकारियों पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित शब्दों में तथ्य के निष्कर्षों को दर्ज किया जो अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निष्कर्षों को प्रभावित नहीं करते थे।

पीठ ने कहा, "यह निर्णय अपीलार्थी के मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि राशि जमा के रूप में वसूल की गई थी। विचाराधीन बिल उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, अपीलार्थी के मामले में राशि को स्वयं अपीलार्थी द्वारा लाभ और हानि खाते में राशि अंतरण करने की कार्रवाई के आधार पर वर्ष की राजस्व रसीद के रूप में माना गया है। उन्हीं कारणों से अपीलार्थी द्वारा उद्धृत अधिकरण का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि अधिकरण द्वारा तय किए गए मामले में बिक्री कर की राशि 'बिक्री-कर' शैली के खाते के तहत अलग से जमा की गई थी। अपीलार्थी के मामले में महत्वपूर्ण तथ्य कि राशि को वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते के जमा में अंतरित किया गया था, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कंपनी ने स्वयं राशि को जमा के रूप में नहीं, बल्कि आय की मद के रूप में माना था।

(3) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारिती फर्म द्वारा दूसरी अपील में, I.T.A में दिल्ली न्यायाधिकरण 'बी' बेंच के फैसले पर भरोसा करते हुए। नं. 1965-66 के 14957 ने निर्धारिती फर्म की अपील को स्वीकार कर लिया। दिल्ली अधिकरण 'ख' पीठ के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया

गया था कि-"बिक्री कर का अप्रयुक्त रहना, भले ही निर्धारिती द्वारा विनियोजित किया गया हो, निर्धारिती का दायित्व नहीं रह जाता है क्योंकि जमाकर्ता किसी भी समय अपनी जमा राशि वापस ले सकते हैं यदि वह अप्रयुक्त रह गई हो। जमा हमेशा बिक्री-कर जमा की प्रकृति में रहता है और कुछ नहीं।

(4) आयकर अपीलीय अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ ने इस निर्णय का अनुसरण किया और निर्धारिती फर्म के दावे को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात्, राजस्व के आवेदन पर, निर्णय के पूर्व भाग में पुनः प्रस्तुत विधि का प्रश्न हमें निर्दिष्ट किया गया है।

(5) यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अभिलिखित तथ्य का निष्कर्ष कि प्रश्नगत राशि निर्धारिती द्वारा व्यापार रसीद के रूप में प्राप्त की गई थी और यह कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उक्त राशि जमा के रूप में वसूल की गई थी, अपीलीय अधिकरण द्वारा अपास्त नहीं किया गया था। इसलिए, हम तथ्य के इस निष्कर्ष से बंधे हैं। इन तथ्यों पर ही हमें संदर्भित कानून के सवाल का जवाब देना होगा।

(6) इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु तय किया जाना है, वह यह है कि बेची गई वस्तु की कीमत के साथ बिक्री कर एक व्यापारिक रसीद है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह निर्धारित करना होगा कि बिक्री-कर बिक्री-मूल्य का एक अभिन्न घटक है या नहीं? यदि यह पाया जाता है कि बिक्री-कर बिक्री-मूल्य का एक अभिन्न अंग है, तो यह स्पष्ट है कि बेची गई वस्तुओं की कीमत सहित बिक्री-कर एक व्यापारिक रसीद है और यह आयकर के अधीन है। दूसरे शब्दों में, बिक्री के समय लेन-देन की प्रकृति का निर्णय लिया जाना है। इसके बाद की कोई भी घटना, उदाहरण के लिए, जैसा कि वर्तमान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण, विक्रेता से बिक्री कर नहीं लिया गया था, मूल लेनदेन की प्रकृति को नहीं बदलेगा।

(7) बिक्री को पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित किया गया है, जो हरियाणा को भी संशोधित रूप में लागू होता है, निम्नलिखित शर्तों में है:-"2 (क) 'बिक्री' का अर्थ है अनुसूची ग में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं में संपत्ति का कोई हस्तांतरण, नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, लेकिन इसमें बंधक, परिकल्पना, शुल्क या गिरवी शामिल नहीं हैं; स्पष्टीकरण।(1) किराया खरीद या भुगतान की अन्य किस्त प्रणाली पर माल का हस्तांतरण, इसके बावजूद कि विक्रेता मूल्य के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी भी माल का स्वामित्व रखता है, बिक्री माना जाएगा।

(8) उसी धारा के खंड (1) में टर्नओवर को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:-"(i) टर्नओवर में शामिल हैं-(i) दी गई अवधि के दौरान किसी भी डीलर द्वारा वास्तव में की गई बिक्री और खरीद की राशियों और बिक्री खरीद के कुछ हिस्सों का योग सामान्य व्यापार प्रथा के अनुसार नकद छूट के रूप में अनुमत किसी भी राशि से कम है, लेकिन इसमें डिलीवरी के समय या उससे पहले माल के संबंध में डीलर द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रभारित कोई राशि भी शामिल है।

(9) कराधान की घटना अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रदान की गई है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत कर मुक्त घोषित वस्तुओं में विशेष रूप से लेनदेन करने वाले को छोड़कर प्रत्येक विक्रेता, जिसका सकल कारोबार कर योग्य मात्रा से अधिक है, इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस धारा की उप-धारा (5) विक्रेताओं की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में कर योग्य मात्रा को परिभाषित करती है। (10) अधिनियम में कोई अन्य धारा नहीं है, जो क्रेता को बिक्री-कर के भुगतान के लिए

उत्तरदायी बनाती है। यह विक्रेता है, जो माल बेचता है, जो अधिनियम के तहत निर्धारित कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(11) एक विशेष विक्रेता, यह गणना करते समय कि ग्राहकों से कितना पैसा लिया जाना है, प्रभारित किए जाने वाले माल की कीमत के अतिरिक्त बिक्री-कर को अलग से निर्दिष्ट कर सकता है। एक अन्य विक्रेता ग्राहकों से यह बताए बिना कि उनके द्वारा लगाए जा रहे बिक्री-कर की राशि क्या थी, उनके द्वारा निर्दिष्ट उचित मूल्य का भुगतान करने के लिए कह सकता है। “फिर भी, कोई अन्य विक्रेता केवल माल की बिक्री-कीमत लेने का विकल्प चुन सकता है और अपने स्वयं के लाभ से बिक्री कर का भुगतान करने का निर्णय ले सकता है, यदि, बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण, वह बेचे गए सामान पर कम लाभ लेने का निर्णय लेता है। तीनों आवश्यकताओं में, माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए मूल्यवान विचार विक्रेता द्वारा खरीदार से प्राप्त कुल राशि होगी क्योंकि विक्रेता ने ग्राहकों से मांगी गई राशि के भुगतान के बिना ग्राहकों को माल में संपत्ति हस्तांतरित नहीं की होगी। यह विक्रेता पर निर्भर करता है कि वह अपनी पसंद के तरीके से बिल तैयार करे, लेकिन ग्राहकों को तब तक संपत्ति नहीं मिल सकती जब तक कि वे कुल बिल का भुगतान नहीं करते।

अतः यह स्पष्ट है कि माल के अंतरण के लिए विचार क्रेता द्वारा माल के अंतरण के लिए भुगतान की गई कुल राशि होगी और विक्रेता द्वारा प्रभारित कुल राशि संबंधित वर्ष के लिए उसके कारोबार में शामिल की जाएगी। जैसा कि अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रावधान किया गया है, कर की घटना डीलर पर है और जिस क्षण वह अधिनियम की धारा 5 के तहत परिभाषित कर योग्य मात्रा से अधिक हो जाता है, वह बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने माल को खरीदार को देने के लिए विचार के रूप में माल की कीमत के साथ बिक्री-कर वसूल करने का विकल्प चुना है या नहीं।

(12) पंजाब डिस्टिलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, शिमला (1) में रिपोर्ट किए गए एक मामले में निर्धारिती ने देशी शराब के डिस्टिलर के रूप में व्यवसाय किया और अपनी डिस्टिलरी की उपज को लाइसेंस प्राप्त थोक विक्रेताओं को बेच दिया। युद्ध शुरू होने के बाद बोतल खोजने में कठिनाई महसूस की गई जिसमें शराब बेची जानी थी और कमी को दूर करने के लिए, सरकार ने एक योजना तैयार की जिसके तहत डिस्टिलर थोक विक्रेता से उन बोतलों की कीमत वसूलने का हकदार था जिसमें शराब की आपूर्ति की गई थी; सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर, जिसे वह बोतलों को वापस करने पर चुकाने के लिए बाध्य था। सरकारी योजना के तहत निर्धारित मूल्य के अलावा, निर्धारिती ने थोक विक्रेताओं से कुछ अतिरिक्त राशि ली, जिसे प्रतिभूति जमा के रूप में वर्णित किया गया है, सरकार की मंजूरी के बिना और पूरी तरह से निर्धारिती द्वारा अपनी शराब की बिक्री के लिए लगाई गई शर्त के रूप में। जब बोतलें वापस की गईं तो प्रतिभूति जमा के रूप में वर्णित धन भी वापस कर दिया गया था, लेकिन इस मामले में एक लेनदेन में ली गई पूरी राशि वापस कर दी गई थी जब उसमें से 90 प्रतिशत बोतलें वापस कर दी गई थीं। की कीमत। निर्धारिती द्वारा प्राप्त बोतलों को उसके सामान्य व्यापार खाते में दर्ज किया गया था, जबकि अतिरिक्त राशि को 'खाली बोतलें वापसी सुरक्षा जमा खाता' शीर्षक के तहत सामान्य खाते में दर्ज किया गया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए जो प्रश्न उत्पन्न हुआ था, वह यह था कि क्या निर्धारिती को रिफंड किए जाने के बाद बची उन अतिरिक्त राशियों की शेष राशि पर कर लगाने के लिए मूल्यांकन किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती, प्रतिभूति जमा के रूप में वर्णित अतिरिक्त राशि को प्राप्त करने में वास्तव में बोतलों के लिए एक अतिरिक्त मूल्य वसूल कर रहा था और अतिरिक्त

राशि वास्तव में शराब की बिक्री के लिए विचार का एक हिस्सा थी और जो बेचा गया था उसकी कीमत का हिस्सा था; इससे कोई फर्क नहीं पड़ा! कि अतिरिक्त राशि एक अलग खाते में दर्ज की गई थी जिसे 'खाली बोतलें वापसी जमा खाता' कहा जाता था, जिसके लिए बिक्री के लिए विचार किया गया था; एक विशेष तरीके से पुस्तकों में लिखा जाना बंद हो गया; और न ही यह तथ्य कि बोतलों की कीमत का भुगतान किया गया था और जब बोतलें वापस की गई थीं, जबकि 90 प्रतिशत बोतलों को वापस करने पर अतिरिक्त राशि का पूरा भुगतान किया गया था, सवाल को प्रभावित करता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि ली गई अतिरिक्त राशियां बोतलों में शराब की बिक्री के वाणिज्यिक लेन-देन का एक अभिन्न अंग थीं और जब उनका भुगतान किया जाता था, तो वे निर्धारिती के धन थे और उसके बाद निर्धारिती के धन बने रहते थे, वे निर्धारिती की व्यापारिक रसीदें थीं; और इसलिए, किए गए रिफंड के बाद बची इन अतिरिक्त राशियों की शेष राशि कर के लिए आकलन योग्य थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि खाली बोतलों की वापसी के लिए प्रतिभूति के रूप में ली गई राशि को वाणिज्यिक लेनदेन का एक अभिन्न अंग माना गया था। इसलिए, वास्तविक परीक्षा यह है कि बेचे गए माल पर कब्जा और नियंत्रण पारित करते समय निर्धारिती को क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ था। अतः यह स्पष्ट है कि बिक्री-कर बिक्री मूल्य का एक अभिन्न अंग है। चूंकि कर का भार निर्धारिती पर है और क्रेता अधिकारियों को बिक्री-कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए बिक्री मूल्य की वास्तविक सामग्री निर्धारिती द्वारा क्रेता से प्राप्त कुल प्रतिफल है। केवल यह तथ्य कि बिक्री-कर को बिक्री-कर के रूप में दिखाया गया है, इसके व्यापार अनुबंध के चरित्र के अनुबंध को नकारता नहीं है जिसमें एक पक्ष बेचता है और दूसरा पक्ष उस माल को खरीदता है जिसमें व्यवसाय या व्यापार किया जाता था। विक्रेता क्रेता पर कर नहीं लगाता है या क्रेता से कर एकत्र नहीं करता है, लेकिन वह जो करता है वह वस्तुओं की कीमत बढ़ाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक विक्रेता के रूप में वह सकल कारोबार के प्रतीक के रूप में उस पर लगाए गए बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए ढीला नहीं होगा।

(13) मामले के इस पहलू पर उच्चतम न्यायालय ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (2) में विचार किया था, जहां एक तर्क दिया गया था कि बिक्री-कर उपभोक्ता को दिए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर के बजाय विक्रेता पर प्रत्यक्ष कर था। यह सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपतियों द्वारा इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था: -

"अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से और एक आर्थिक सिद्धांत के रूप में, बिक्री-कर उपभोक्ताओं पर एक अप्रत्यक्ष कर हो सकता है, लेकिन कानूनी रूप से ऐसा होना आवश्यक नहीं है। 1947 के अधिनियम के तहत, जहां तक राज्य का संबंध है, बिक्री कर का भुगतान करने का प्राथमिक दायित्व विक्रेता पर है। वास्तव में संशोधन अधिनियम द्वारा 1947 के अधिनियम के संशोधन से पहले, विक्रेताओं को खरीदार से बिक्री-कर वसूलने का कोई अधिकार नहीं था। विक्रेता निःसन्देह बिक्री-कर को शामिल करने के लिए कीमत लगा सकता था, जिसका उसे भुगतान करना पड़ता, लेकिन वह खरीदार से कोई बिक्री-कर वसूल नहीं कर सकता था। यह परिस्थिति विक्रेता पर लगाए गए बिक्री-कर को माल की बिक्री पर किसी भी तरह से कम बिक्री-कर होने से नहीं रोक सकती। यह परिस्थिति कि 1947 के अधिनियम ने संशोधन के बाद, विक्रेता, जो एक पंजीकृत विक्रेता था, को खरीदार से कर के रूप में बिक्री-कर एकत्र करने की अनुमति दी थी, बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए विक्रेता के प्राथमिक दायित्व को समाप्त नहीं करता है। यह इस तथ्य से और स्पष्ट हो जाता है कि पंजीकृत विक्रेता को, यदि वह चाहे या चाहे, तो खरीदार से कर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है और कभी-कभी अन्य पंजीकृत विक्रेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण उसे अपना माल बेचना

और बिक्री कर के त्याग पर भी अपने पुराने ग्राहकों को बनाए रखना लाभदायक लग सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बिक्री-कर खरीदारों को देने की आवश्यकता नहीं है और यह तथ्य उस कर की वास्तविक प्रकृति को नहीं बदलता है जो कानून के स्पष्ट प्रावधान द्वारा विक्रेता पर डाला जाता है। खरीदार पर सहमत बिक्री मूल्य के अलावा बिक्री-कर का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है जब तक कि अनुबंध विशेष रूप से अन्यथा प्रदान नहीं करता है।

(14) सर्वोच्च न्यायालय के इन अवलोकनों से सबसे पहले यह संकेत मिलता है कि बिक्री कर की राशि भले ही लेन-देन में बिक्री-कर के रूप में अलग से दर्शाई गई हो, उस प्रतिफल का एक हिस्सा है जो विक्रेता संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में और प्रतिफल के हिस्से के रूप में लेता है; दूसरा, विक्रेता खरीदार से बिक्री कर ले सकता है या नहीं ले सकता है, लेकिन इससे बिक्री या खरीद के लेन-देन के कानूनी स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। ऊपर जो कहा गया था, उससे यह स्पष्ट है कि निर्धारिती द्वारा अपने खरीदारों से प्राप्त बिक्री-कर बिक्री मूल्य का एक अभिन्न अंग था और यह पूरी तरह से महत्वहीन है यदि निर्धारिती उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णय के कारण बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। यह फिर से पूरी तरह से महत्वहीन है यदि खरीदार बाद में किसी समय निर्धारिती से उक्त कर वापस लेने का दावा करने का हकदार है। जहां तक आयकर अधिनियम के प्रावधानों का संबंध है, बिक्री-कर सहित सुसंगत निर्धारण वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त कुल राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 (i) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए एक व्यापारिक रसीद होगी, जो निम्नलिखित शर्तों में हैं:-"28. निम्नलिखित आय 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ:-(i) किसी व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ जो निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किए गए थे' शीर्ष के तहत आयकर के लिए प्रभार्य होगी।

(15) यदि और जब निर्धारिती क्रेताओं को उनकी मांग पर प्रश्नगत राशि का भुगतान करता है, तो निर्धारिती उस निर्धारण वर्ष में राहत की मांग करने का हकदार हो सकता है जिसमें प्रश्नगत राशि का भुगतान किया जाता है, लेकिन जहां तक उस निर्धारण वर्ष का संबंध है जिसमें राशि प्राप्त की गई थी, तो बिक्री-कर सहित निर्धारिती द्वारा प्राप्त कुल राशि एक व्यापारिक रसीद है और आयकर के लिए उत्तरदायी है।

(16) यह उच्चतम न्यायालय द्वारा मेसर्स जॉर्ज ओक्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम मद्रास राज्य और अन्य में रिपोर्ट किए गए एक मामले में आयोजित किया गया था। (3) कि जब विक्रेता कर देता है और क्रेता मूल्य के अतिरिक्त विक्रय-कर का भुगतान करने के लिए सहमत होता है, तो कर वास्तव में संपूर्ण प्रतिफल का हिस्सा है और दो राशियों-कर और मूल्य-के बीच का अंतर सभी महत्व खो देता है।

(17) छत्रसिंहजी केसरसिंहजी ठाकुर बनाम आय-कर आयुक्त, बंबई नगर 2 (4) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जब किसी निर्धारिती को संविदा के अधीन निश्चित रकम प्राप्त हुई थी और यदि वह राशि आय थी, तो यह तथ्य कि जिस व्यक्ति ने उसका संदाय किया है वह उसके प्रतिदाय का दावा कर सकता है, उक्त नियम को उस वर्ष में उसके आय के स्वरूप से वंचित नहीं करेगा जिसमें वह प्राप्त किया गया था। उस मामले में निर्धारिती ने एक खनन पट्टा प्रदान किया और पट्टेदार ने किराए और रॉयल्टी के अलावा, सार्वजनिक मांगों की प्रकृति में सभी करों, दरों, निर्धारणों और अधिरोपणों का भुगतान करने का बीड़ा उठाया, जो भूमि राजस्व की मांगों को छोड़कर पट्टेदार की खानों और कार्यों या उसके किसी भी हिस्से पर या उनके संबंध में लगाए जा सकते हैं। पट्टेदार ने पट्टेदार को यह विश्वास करते हुए कुछ राशियों का भुगतान किया कि वह भाग VII के खंड I के तहत

अपीलार्थी को प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी था, किराए और रॉयल्टी की राशि के रूप में 3 आना की दर से उपकर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि उन्हें भुगतान से सीधे संबंधित एक वाचा के तहत भुगतान किया गया था, इसलिए वे कर योग्य आय भी थीं: यह मायने नहीं रखता था कि यदि वास्तविक स्थिति की सराहना की जाती है, तो पट्टेदार ने राशि का भुगतान नहीं किया होगा। वास्तव में पट्टेदार द्वारा राशियों का भुगतान किया गया था और अपीलार्थी द्वारा प्राप्त और विनियोजित किया गया था जैसे कि वह उन्हें प्राप्त करने का हकदार था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी को प्राप्त राशियों और पट्टा दावा प्रतिपूर्ति की शर्तों के अधीन प्राप्त राशियों के बीच अंतर को, इसलिए, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अर्थ के भीतर आय के रूप में माना जाना था और जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी गई हो, कर के लिए उत्तरदायी थे। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह तथ्य कि पट्टेदार धनवापसी का दावा कर सकता है, उस वर्ष में उनकी आय के चरित्र के भुगतान से वंचित नहीं करता है जिसमें वे प्राप्त हुए थे। उस मामले में पट्टेदार ने वास्तव में धनवापसी की वापसी के लिए एक मुकदमा दायर किया था, लेकिन फिर भी यह माना गया कि संदर्भ के तहत किसी विशेष वर्ष में भुगतान की प्राप्ति उसके व्यापारिक रसीद के चरित्र से वंचित नहीं करेगी। इसलिए, यह आयकर के लिए उत्तरदायी था।

(18) लखनंदी कोल कंपनी बनाम आयकर आयुक्त, कलकत्ता (5) निर्धारिती को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप बंबई विक्रय-कर प्राधिकरण के आदेश के परिणामस्वरूप विक्रय-कर का प्रतिदाय प्राप्त हुआ। आयकर अधिकारियों ने इस वापसी की गई राशि का आकलन निर्धारिती की आय के रूप में करने की मांग की। निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया था कि बिक्री-कर निर्धारिती द्वारा निर्धारिती के खरीदारों से एकत्र किया गया था, और यह बिक्री-कर अधिकारियों को भुगतान किए जाने वाले कानून के तहत था और जब बिक्री-कर का प्रतिनिधित्व करने वाले धन को बिक्री-कर अधिकारियों द्वारा वापस कर दिया गया था, तो वही धन निर्धारिती द्वारा निर्धारिती के खरीदारों को वापस कर दिया गया था, और इसलिए, वापस की गई राशि उसकी आय के रूप में आकलन योग्य नहीं थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बिक्री-कर की राशि, भले ही बिक्री कर के रूप में बिक्री के लेन-देन में अलग से दिखाई गई हो, उस प्रतिफल का एक हिस्सा है जो विक्रेता संपत्ति के हस्तांतरण के लिए लेता है। यह तथ्य कि कानून में यह प्रावधान है कि विक्रेता बिक्री-कर एकत्र कर सकता है, उसके व्यापारिक चरित्र के लेन-देन को नहीं लूटा और परिणामस्वरूप, विचाराधीन राशि निर्धारिती की आय के रूप में आयकर के लिए आकलन योग्य थी। उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों के समान हैं सिवाय इसके कि इकराहनादी कोयला कंपनी के मामले में (5) (उपर्युक्त) बिक्री-कर का भुगतान किया गया था और उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण निर्धारिती को उसी का भुगतान किया गया था कि वह देय नहीं था और वर्तमान मामले में निर्धारिती ने बिक्री-कर बिल्कुल भी जमा नहीं किया था क्योंकि इसे जमा किए जाने से पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि ऐसा कर हाथ में लेनदेन पर देय नहीं था।

(19) इसी प्रकार का प्रश्न आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष बट्टी नारायण बालाकिशन बनाम आय-कर आयुक्त, आंध्र प्रदेश (6) में रिपोर्ट किए गए एक मामले में उत्पन्न हुआ, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निक्षेपों या प्रतिभूति जमाओं के मामले में लागू सिद्धांत यह है कि जहां यह मूल्य का भाग है या प्रत्येक लेन-देन का भाग है, क्या राशि वापसी योग्य है या नहीं, यह एक व्यापारिक रसीद मानी जाती है। लेकिन यदि प्राप्त राशि का लेन-देन से कोई लेना-देना नहीं है या मूल्य का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन केवल किसी दायित्व या सेवा के उचित प्रदर्शन के

लिए प्राप्त की जाती है, तो इसे व्यापारिक रसीद के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि उधार ली गई राशि के समान है। उक्त मामले में, निर्धारिती ने ग्राहकों से बिक्री-कर के माध्यम से राशि एकत्र की थी और इसे एक अलग खाते में जमा किया था जिसे जमा खाता कहा जाता है। यह तथ्यों पर अभिनिर्धारित किया गया था कि राशि प्रत्येक लेन-देन का हिस्सा थी और निर्धारिती द्वारा लगाए गए मूल्य का हिस्सा थी।

फलस्वरूप इन राशियों का व्यापार प्राप्तियों के रूप में आकलन किया जा सकता था। वर्तमान मामले में, जैसा कि मैंने पहले ही अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष का उल्लेख किया है कि निर्धारिती के नेतृत्व में कोई सबूत नहीं था कि प्रश्नगत राशि जमा के रूप में वसूल की गई थी, बरकरार है और तथ्य के उक्त निष्कर्ष पर न तो अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष हमला किया गया था और न ही इस पर हमला करने की मांग की गई थी) हमारे सामने कानून का सवाल उठाते हुए, यदि इसे उठाया जा सकता है, तो न्यायाधिकरण के समक्ष इस कानून के प्रश्न को हमारे पास भेजने के लिए। इसलिए, तथ्य का यह निष्कर्ष हम पर बाध्यकारी है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रश्नगत राशि जमा के रूप में वसूल नहीं की गई थी, इसलिए निर्धारिती द्वारा वसूल की गई बिक्री-कर की राशि स्पष्ट रूप से बिक्री मूल्य का एक अभिन्न घटक थी और यह आयकर के अधीन है।

(20) आयकर आयुक्त, कलकत्ता बनाम सिनक्लेयर मुर्रे एंड कंपनी (पी) लिमिटेड (7) में रिपोर्ट किए गए एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया था:- "यदि बिक्री-कर वैध रूप से प्रत्यक्ष है और एक विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक से वसूल किया जाता है, और फिर अपने व्यवसाय में उपयोग किया जाता है, तो इस तरह से उठाया गया कर बिक्री मूल्य के हिस्से के अलावा नहीं हो सकता है। इसलिए, इसे व्यापारी की व्यापारिक रसीद में शामिल किया जाना चाहिए और यह आयकर अधिनियम के उद्देश्य के लिए आय बन जाती है, इसका सरल कारण यह है कि कर के रूप में खरीदार से प्राप्त धन का उपयोग व्यापारी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है और कर को मूल्य सरलीकरण से अलग नहीं किया जाता है।

(21) उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि 'निर्दिष्ट विधि के प्रश्न का उत्तर हमें नकारात्मक रूप में देना होगा।

(22) निर्धारिती की ओर से, मुख्य निर्भरता मैसूर राज्य पर रखी जा रही है और एक अन्य बनाम मैसूर स्पिनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और एक अन्य (8). उस मामले में मैसूर बिक्री कर अधिनियम की धारा 11 (1) (2) के प्रावधानों की जांच की जा रही थी जो इस प्रकार हैं: - "11(1). कोई भी व्यक्ति, जो पंजीकृत विक्रेता नहीं है, इस अधिनियम के तहत कर के रूप में कोई राशि एकत्र नहीं करेगा; और न ही एक पंजीकृत विक्रेता ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों, यदि कोई हो, के अनुसार, जो निर्धारित किया जा सकता है, के अलावा ऐसा कोई संग्रह करेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई राशि एकत्र करता है, सरकार को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे संग्रह का भुगतान करेगा जो उस अवधि के लिए उसके द्वारा भुगतान किए गए कर से अधिक है, जिसके दौरान संग्रह किए गए थे या, यदि उसने प्रश्नगत अवधि के लिए कोई राशि का भुगतान नहीं किया है, तो वह सरकार को अपने द्वारा इस प्रकार एकत्र की गई सभी राशियों का भुगतान करेगा; और इस तरह के भुगतान की चूक में, (राशियों को वसूल किया जा सकता है जैसे कि वे भूमि राजस्व के बकाया थे।

(23) उस मामले में एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या अधिनियम की धारा 11 (2) में उस अधिनियम के तहत कर के रूप में एकत्र की गई राशियों के संदर्भ का अर्थ निर्धारिती द्वारा एकत्र किया गया सभी कर हो सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि क्या वह अधिनियम के तहत उसे एकत्र कर सकता है या नहीं, और अधिनियम की धारा 11 की

उप-धाराओं (1) और (2) की व्याख्या करते हुए, मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "कर के रूप में एकत्र की गई राशि! अधिनियम की धारा 11 (2) में इस अधिनियम का अर्थ केवल उन बिक्री-लेन-देनों के संबंध में एकत्रित राशियों से हो सकता है जिन पर बिक्री-कर का प्रभार संवैधानिक रूप से अधिरोपणीय है और अधिनियम द्वारा तथ्यात्मक रूप से अधिरोपित है। उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा हमला किया जा रहा था। इस तर्क की उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई थी और मामले के स्वीकृत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विचाराधीन धन को अधिनियम की धारा 11 (2) के अर्थ के भीतर "संग्रह" नहीं कहा जा सकता है। यह मैसूर स्पिनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट है (8) (उपर्युक्त) "धारा 11 की उपधारा (1) और (2) में आने वाले" "इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में" "शब्दों की उचित व्याख्या के संबंध में दोनों पक्षों के विद्वत वकीलों द्वारा उपर्युक्त तर्ज पर दिए गए तर्कों के बाद,-"

यह महसूस किया गया कि इन सभी मामलों के तथ्यों पर, कोई 'संग्रह' नहीं था, चाहे 'कर के रूप में' या अन्यथा, ताकि उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त और रखी गई राशियों को धारा 11 के दायरे में लाया जा सके। हमने पहले ही निर्दिष्ट प्रश्नों को निर्धारित कर दिया है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि राशि सीमेंट मार्केटिंग कंपनी और मैसूर स्पिनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी और मिनर्वा मिल्स लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई थी, केवल एक संभावित आकस्मिकता को कवर करने के लिए 'जमा' के रूप में इन कंपनियों को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। यह कि लेन-देन की वास्तविक प्रकृति यही थी, कभी भी विवाद में नहीं था। वास्तव में बिक्री-कर आयुक्त ने भी तीन मामलों में निर्देश देते हुए यह स्पष्ट किया कि राशियां कंपनियों द्वारा इस निश्चित समझ और शर्त पर प्राप्त की गई थीं कि उन्हें केवल 'जमा के रूप में' वापस किया जाना था, जब कंपनी अपने कर योग्य कारोबार में प्रासंगिक बिक्री को शामिल करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। जिस आधार पर विक्रय-कर प्राधिकरणों ने कार्यवाही की वह यह थी कि अधिनियम में एक प्रकार की रसीद और दूसरे के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था, और यह कि खरीदार से किसी व्यापारी द्वारा धन की कोई भी प्राप्ति अधिनियम की धारा 11 (2) के भीतर 'कर के रूप में संग्रह' थी, बशर्ते कि इसका बिक्री-कर से कुछ संबंध था, और यह मायने नहीं रखता था कि रसीद केवल संदेहास्पद खाते में ले जाने वाले दाता द्वारा जमा की गई थी, एक्सप्रेस अंडरटेकिंग पर प्राप्त की जा रही राशि और निश्चित शर्त कि डीलर को उस लेनदेन पर बिक्री-कर के लिए उत्तरदायी नहीं होने की स्थिति में वापस किया जाएगा जिसके संबंध में 'जमा' किया गया था। हम अधिनियम की धारा 11 (2) में आने वाली अभिव्यक्ति 'संग्रह' के इस निर्माण में सहमत होने में असमर्थ हैं। जहां इन मामलों में व्यक्त समझ या वचन पर केवल जमा के रूप में राशि प्राप्त की जाती है, कंपनी ने धन को केवल संरक्षक के रूप में रखा और शर्त की पूर्ति पर जमाकर्ता का न्यासी बन गया। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि जब एक बार कर अधिकारियों ने यह निर्धारित किया कि विचाराधीन बिक्री की आय कंपनी के कर योग्य कारोबार के भीतर नहीं थी, तो लाभकारी स्वामित्व जमाकर्ताओं में निहित हो गया और कंपनी को धन रखने का कोई अधिकार नहीं रहा। यह तथ्य कि 'जमाकर्ता' से 'विक्रेता' को पारित धन का भौतिक नियंत्रण अधिनियम की धारा 11 (2) के भीतर रसीद को 'संग्रह' नहीं बनाता है।

(24) यह प्राधिकरण वर्तमान मामले में निर्धारिती के लिए कोई सहायक नहीं है। सबसे पहले, इस मामले में यह एक तथ्य के रूप में पाया गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वर्तमान मामले में खरीदारों ने विक्रेता के पास इस स्पष्ट समझ या वचन पर बिक्री कर जमा किया है कि यदि निर्धारिती को आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया

गया था तो खरीददारों को पैसा वापस कर दिया जाएगा: इसके कर योग्य कारोबार में प्रासंगिक निर्धारण वर्ष। दूसरी ओर, अभिलिखित तथ्य का निष्कर्ष यह है कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उक्त राशि जमा के रूप में वसूल की गई थी। विचाराधीन बिल उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, निर्धारिती ने स्वयं उक्त राशि को लाभ और हानि खाते में अंतरित करने की अपनी कार्रवाई के आधार पर वर्ष 1963-64 के लिए राजस्व रसीद के रूप में माना। ऊपर निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय प्राधिकरण में, उनके अधिपत्यों ने विशेष रूप से निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया:- "हमें यह कहने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि एक विक्रेता द्वारा एक खरीदार द्वारा उन राशियों का संग्रह जो उसके द्वारा कानूनी रूप से मांग योग्य नहीं हैं, धारा 11 के भीतर 'संग्रह' नहीं हैं, केवल इसलिए कि खरीदार कानूनी रूप से धनवापसी के लिए दावा कर सकता है और उचित कार्यवाही में उस अधिकार को लागू कर सकता है। लेकिन ऐसा मामला हमारे सामने वाले मामलों से बहुत अलग है, जहां खरीदार द्वारा भुगतान सशर्त था और एक स्पष्ट अनुबंध पर किया गया था कि विक्रेता को प्रासंगिक कारोबार के संबंध में आकलन योग्य नहीं होने की आकस्मिकता में राशि वापस कर दी जाएगी।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि ऊपर निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के मामले में यह तथ्यों पर पाया गया कि प्रश्नगत राशि निर्धारिती द्वारा क्रेता से व्यक्त वचन पर प्राप्त की गई थी कि यदि निर्धारिती को उसके कर योग्य कारोबार में सुसंगत बिक्री को शामिल करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था तो वह राशि क्रेता को वापस कर दी जाएगी, जबकि वर्तमान मामले में तथ्य का एक स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रश्नगत धन निर्धारिती द्वारा जमा के रूप में प्राप्त किया गया था, धनवापसी के किसी भी स्पष्ट वचन के साक्ष्य के बिना। इसलिए, केवल इसी आधार पर, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि यह प्राधिकरण निर्धारिती के लिए कोई सहायक नहीं है। इसके अलावा, उक्त मामला केवल मैसूर बिक्री कर अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों में निहित 'संग्रह' शब्द की व्याख्या तक ही सीमित था और यह आयकर अधिनियम के तहत मामला नहीं था। आयकर अधिनियम की योजना में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि व्यापार रसीद के रूप में जो भी राशि वसूल की जाती है, वह आयकर के अधीन है।

इस सवाल पर कि क्या लगाया गया बिक्री कर व्यापार रसीद का एक अभिन्न अंग है या नहीं, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था।

(25) यह तर्क कि जिस क्षण कोई क्रेता निर्धारिती से उसके द्वारा संदत्त विक्रय कर की विवरणी की मांग करता है, जो प्रभार्य नहीं था, निर्धारिती उसे लौटाने के लिए बाध्य है, इसलिए यह राशि आयकर में प्रभारित नहीं की जानी चाहिए, बिना किसी योग्यता के है। संबंधित निर्धारण वर्ष में निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि निश्चित रूप से एक व्यापारिक रसीद है जैसा कि उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है और इसे उक्त प्रासंगिक वर्ष के लिए प्रभारित करना होगा। यदि और जब कोई खरीदार निर्धारिती से राशि की वापसी की मांग करता है और निर्धारिती वास्तव में उस राशि का भुगतान करता है, तो यह निर्धारिती के लिए उस राशि के बारे में उस समय राहत का दावा करने के लिए खुला होगा जब इसे वापस किया जाता है। इसी तरह का दृष्टिकोण कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सिनक्लेयर मरे के मामले में लिया गया था

(7) (supra).

(26) निर्धारिती द्वारा सुसंगत निर्धारण वर्ष में प्राप्त राशि उसकी व्यापार रसीद थी और उसने उक्त राशि का उपयोग अपने व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपने व्यवसाय के दौरान इस राशि को आगे बढ़ाया और इसलिए, यह आयकर के लिए उत्तरदायी है। ऊपर जो कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि हमें निर्दिष्ट किए गए प्रश्न का उत्तर यह है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, न्यायाधिकरण रुपये की राशि को निर्धारण से बाहर करने में कानूनी रूप से उचित नहीं था। 4, 155 बिक्री कर जमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, संदर्भ का उत्तर लागत के रूप में बिना किसी क्रम के नकारात्मक में दिया जाता है।
न्यायमूर्ति पंडित, -में सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पीयूष चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा